

### Compensation by the State to the Victims of hit-and-run Cases

9456. SHRI D. K. PANDA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Law Commission has recommended that State should undertake the responsibility to compensate the victims of hit-and-run cases of car accidents; and

(b) if so, what decision has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI M. B. RANA): (a) Yes, Sir.

(b) Since the implementation of the recommendation of the Law Commission involves amendment to the Motor Vehicles Act, 1939, it is being circulated to the State Governments and Union Administrations for comments, as suggested by the Commission themselves. A decision will be taken after comments are received from the State Governments etc.

12 Hrs.

### CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported consensus on Cauvery Waters between the Chief Ministers of Tamil Nadu, Mysore and Kerala

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालिअर): अध्यक्ष महोदय, मैं अखिलभारतीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर मिचार्ड और विद्युत मंत्री का ध्यान दिनाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह हम बारे में एक वक्तव्य दें।

"कावेरी तथ्य जोष समिति द्वारा कावेरी जल के संबंध में की गई परिगणना के बारे में तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुख्य मंत्रियों के बीच मतैक्य का समाचार"

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA): There have been differences amongst the States of Kerala, Mysore and Tamil Nadu for a number of years on the Cauvery waters. The discussions held in May, 1972 amongst the Chief Ministers revealed the general consensus that a serious attempt should be made to resolve the dispute by negotiations as early as possible. There was also consensus that the Centre should appoint a Fact Finding Committee to collect all the connected data pertaining to Cauvery waters, their utilisation and irrigation practices as also about projects both existing, under construction and proposed in the Cauvery basin. The Committee should also examine the adequacy of the present supplies or excessive use of water for irrigation purposes.

A Fact Finding Committee was accordingly set up by Government of India on 12th June, 1972 and had the following composition—

1. Shri Justice B. D. Bal—Retd. Judge of Bombay High Court.
2. Shri P. R. Ahuja—Retd. Commissioner (Indus) and Joint Secretary, Ministry of Irrigation and Power.
3. Shri Jatindra Singh—Retd. Chief Engineer, Punjab.
4. Dr. J. S. Patel—Retd. Agricultural Commissioner, Ministry of Food & Agriculture.

The Committee submitted its report in December, 1972, which contains the necessary data on the availability of waters, existing utilisation as reported to the Committee, utilisation proposed from projects under construction and the utilisation envisaged from future projects contemplated by the three States.

There were discussions with the Chief Ministers of Kerala, Mysore and Tamil Nadu on 29th April, 1973 about the report of the Committee. During these discussions, there was a general consensus

[Shri Balgovind Verma]

on the total yield of the river as given in the Committee's Report. As desired by the Chief Ministers, the Committee is being revived to furnish clarifications on some other points after such verification as is found necessary.

The Chief Ministers agreed to meet at a later date to continue the discussions and explore the possibilities of arriving at a settlement.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय कावेरी हमारी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नदियों में से है। केरल मैसूर और तमिलनाडु का प्रदेश कावेरी के द्वारा अभिसिंचित होता है। इन प्रदेशों में इस नदी के जल विवाद को ले कर काफी दिना स विवाद चल रहा है। मंत्री महोदय न इस वक्तव्य में कहा है कि अभी 29 अप्रैल का जा मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी उस में इस सवाल पर मतभेद हो गया कि कावेरी में से कुल कितना जल उपलब्ध होगा। यह तथ्य तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सामने आ गया है लेकिन क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विवाद इन वर्षों से चल रहा है और सेंट्रल वाटर रीड पावर कमिशन या सरकार के किसी अंग एजेंसी न यह पता तक लगाने का प्रयत्न नही किया कि जितनी पानी के लिये सगुआ 21 रहा है वह कुल कितना है? अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उस न कहा है कि पानी कुल 21 मिलियन क्यूबिक मीटर उपलब्ध है, लेकिन तीनों राज्य जा पानी माग रहे हैं वह 35 मिलियन क्यूबिक मीटर है। मुझे तो लगता है कि मुख्य मंत्रियों की बैठक विफल हो गई या फिर मुख्य मंत्रियों की बैठक न जा विवाद का मुख्य मुद्दा है उस को स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। मुख्य मुद्दा यह है कि पानी का वितरण किस हिसाब में हो।

तमिलनाडु कह रहा है कि कावेरी का पानी के संबंध में 1924 में और उस से भी पहले 1892 में समझौता हुआ था। यह समझौता मद्रास और मैसूर के बीच में हुआ था। उस समझौते के अनुसार तमिलनाडु ने सिंचाई के प्रबंधों का विकास किया और अब तमिलनाडु यह चाहता है

कि ऐसा समझौता हो जिस से तमिल और त्रिपुरा-पल्लो जिलों का जो भूखण्ड है, जो कावेरी के जल से सिंचित हो रहा है, उस भूखण्ड को जल से वंचित न रहना पड़े। तमिलनाडु यह भी चाहता है कि जब तक विवाद तय न हो तब तक मैसूर की कावेरी या उस से जुड़ी हुई नदियों पर नई परियोजनाएँ बनने से रोक दी जायें। इस के विपरीत मैसूर का कहना यह है कि 1424 का जो समझौता था वह असामान्य समझौता था, उस में मैसूर का पक्ष ठीक तरह से नहीं रखा गया था। मैसूर अब नई योजनाएँ हाथ में ल रहा है। वह 1924 के ऐग्रीमेंट से बंधा रहने के लिये तैयार नहीं है। उसने कई योजनाएँ अपन हाथ में ली हैं। हेमावती हरणी और कन्नौरी परियोजनाएँ दस वर्षों से चल रही हैं। इन परियोजनाओं के लिये प्लानिंग कमिशन की स्वीकृति नहीं ली गई। परियोजनाओं को पूरा करने में धन का अभाव है लेकिन मैसूर अपने हित की दृष्टि से इन परियोजनाओं को पूरा करना चाहता है।

तीसरी आग करल का सवाल है। जब मद्रास और मैसूर का समझौता हुआ तो बेरा की उपेक्षा की गई। केरल का दावा यह है कि पानी सब से ज्यादा बहा बरसता है इसलिए कावेरी का पानी दन में उस का सब से ज्यादा वागदान है

"One-third of the run off of the basin is made by the catchment area lying in the State on account of the very heavy rainfall"

में जानना चाहता हू कि जन के वितरण के सम्बन्ध में जा विवाद है वह कैसे हल होगा? मंत्री महोदय ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिवाइव किया जा रहा है

"As desired by the Chief Ministers the Committee is being revived to furnish clarifications on some other points after such verifications as are found necessary"

में जानना चाहता हू कि वह कौन सा क्लैरिफिकेशन है जो मागा गया है और कौन से बेरिफिकेशन

हैं जिन की आवश्यकता है। क्या इस में जल के वितरण का भी मसाला है ?

नीसरा प्रश्न यह है कि यह नदी तीन प्रदेशों की विभाई करती है, इस लिये अभी तक विवाद को हल क्यों नहीं किया गया ? जब वितरण का प्रश्न धार्येगा तब केन्द्र द्वारा नये मुद्दे खड़े किये जायेंगे। क्या हम मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह भी चर्चा की गई कि अगर अन्ततोगत्वा तीनों मुख्य मंत्रियों का समझौता न हुआ तो इस मामले को ट्राइब्यूनल को सौंप दिया जाये ? ससद् इस तरह का कानून बना चुकी है और ट्राइब्यूनल का निर्णय तीनों पक्षों को मान्य होगा, इस बात की मांग की जा सकती है। तीनों पक्ष उस को मानने से बच्चे भी हुए हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक यह विवाद चलता रहेगा और कब तक हम राष्ट्रीय जल का पूरा उपयोग करने में असमर्थ रहेंगे। क्या धारगे मुख्य मंत्रियों की बैठक के लिए कोई तारीख भी तय हुई है या नहीं ? जो पिछली बैठक हुई है, क्या उस में वितरण के बारे में भी कोई चर्चा हुई है ? धारणा यह बनी है कि मुख्य मंत्रियों में कानसेन्स हो गया है। किम बारे में कानसेन्स हो गया है ? कानसेन्स ता कैन्ट फार्डिङ कमेटी को रिपोर्ट के बारे में हुआ है कि कितना पानी उपलब्ध है ? लेकिन झगडा है पानी के वितरण के बारे में और वह झगडा अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या मनी महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि मारा मामला ट्राइब्यूनल को सौंप दिया जाये, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का हल निकाला जाये और जब तक ट्राइब्यूनल अपना फैसला नहीं देना, तब तक जहा परियोजनाये बना कर भूमि सीधी जा रही है, चाहे वह मैसूर में हो और चाहे तामिलनाडू में हो,—और वह अधिकतर तामिलनाडू में है, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है—बहा सिंचित भूमि को असिंचित बनाने के लिए कोई प्रयत्न न किया जाये ?

**THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO):** As the hon. Member has said, the Cauvery is one of our most ancient and sacred rivers, and one of those rivers in the world, of whose waters much use has been made.

The hon. Member has mentioned various difficulties that have arisen in the Cauvery system. There are three aspects which have got to be resolved in any river dispute. The first is the quantum of water which is there in the river. That is the first aspect which has got to be decided. The second is the allocation among the different contending parties, namely how much amount of water should be allocated to one State, how much to the other and so on. The third is the regulation, that is, how the regulation of the water is to be done so that each of the contending parties will get the water which has been allocated. These are the three important aspects which have to be settled in any river dispute.

There are a number of disputes where there has been difficulty in fixing the quantum of water. For example, in the Krishna river, more than four years have passed in the Tribunal trying to find out the quantum of water which is there in the river. That is one of the very difficult items to be settled. The Government of India have only recently been able to survey some of the basins of the river. This problem arises in regard to the various rivers flowing through the various States.

Therefore, wherever there is a river dispute, the first question that presents considerable difficulty is the fixing up of the quantum of water that flows in the river.

In this particular case, the quantum of water flowing in the river has been agreed to as between the three parties. That is a great thing which has been done. Normally they could have easily agreed in regard to the quantum at one point. But in this case, actually, they have agreed at three vital points, namely Krishna-  
rajasagar, Mettur and Lower Anicut. These are the three very important points which have got a bearing on the settlement of the allocation of water between the various States, and I am happy that on this matter, at these three points, at the very first meeting, after the fact-finding committee published their report, the

[Dr. K. L. Rao]

three Chief Ministers have agreed to it. That is half the battle won.

Then comes the question of allocation of these waters. When they came to the allocation of water, what the hon. Member said was this. The fact-finding committee has given some figures in regard to the area involved, that is, the cropped area in the Cauvery basin, that is, the area that has been irrigated in the various States and the amount of water that has been utilised. They have taken these figures from those that have been given to them by the various States. They have not verified them from any other statistical facts, but they have simply taken the figures given by the States.

One of the important factors in allocation of water will be the percentage of irrigation that has been done in the various States, how much per cent has been irrigated in Tamil Nadu, how much in Mysore and how much in Kerala. That is a very important factor in the allocation of waters. What the fact-finding committee has said is that they have taken the figures as they were given by the States. They could not do anything further, because they were not furnished with any other information. Now, the Chief Ministers have agreed to give them all the publications on the subject, such as crop data from the revenue point of view, statistical books and so on, and they have got to verify whether the figures already supplied by the Chief Ministers are comparable or they require any modification. In other words, after verification, they must come to an agreement on the cropped areas, the irrigated areas and the water that is also utilised. That is another point. We have also asked the committee to find out what is the amount of water utilised is and whether the utilisation excessive, is too much or too little; to give us their opinion. That is the information we want them to give confidentially to us. So, once we have this information, it will be possible for us to take the next step of allocating the waters among these States.

I attended that meeting and from what I have seen, I have found extreme cordiality and the will to settle this problem among themselves. I only hope that in the course of the next two or three months it will be possible for us to tackle this problem.

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :**

Sir, I referred to the agreement of 1924 between Madras and Mysore and the view that the present Mysore Government holds, namely, that the agreement is dead. Does the hon. Minister agree with that view?

**DR. K. L. RAO :** I did not purposely say anything on that, because I did not want to give my views on it. The 1924 agreement was concluded between the then Madras Government and Mysore; it is for a period of 50 years. I do not want to go into the validity or otherwise of it. We are trying to settle the dispute amicably irrespective of any kind of agreement like that which had been made during the previous periods.

**SHRI P. GANGADEB (Angul) :** Mr Speaker, Sir, the Cauvery river water dispute among the three States of Tamil Nadu, Mysore and Kerala has been a long-drawn wrangle, and the inordinate delay in its settlement is a matter of concern to the nation as a whole. Let us not forget that river waters are very much a precious national resource, and its value we know only in its absence. But the unfortunate part of it is that the series of disputes among the various States over this India water, if I may call it, either of Cauvery water or other inter-State river waters, go to show that even when water is available, its value is not sufficiently recognised. Consequently, water resources are neither conserved for the present generation nor for the posterity to benefit from its usage. Unless a permanent and early solution is found to this perennial problem, and unless that is done we will never have water for our fields, nor power for our industries.

This House is well aware that irrigation and river water management are State subjects under the Constitution. In that set-up, we find each State has its vested interests, whether it is in the use of water or power resources and potentialities. It seems as though, the river water disputes these days are more politics and less economics. What is happening is that, on the one hand, some States fail to utilise the surplus waters available within their borders, and, on the other hand, their neighbours are made to suffer for want of sufficient water. One, therefore, wonders who is to be accused and on whom the responsibility falls to ensure an equitable distribution of water resources all over our country.

The constitutional position is indeed anomalous. Merely on the ground that it is a State subject under the Constitution, can the Centre just sit and watch the dispute to be solved by themselves? In the meantime, while some States suffer for want of water due to scarcity and drought, others just allow the invaluable waters to go waste. It is a very important matter to think of. If I may say so, we are up against a man-made problem. Therefore, the Centre has to find a man-made solution. Let us think in terms of national interests and devise means to solve this problem.

I would, therefore, like to suggest firstly that the Government should consider creating viable economic zones for the management of this vital national wealth like river water. Let us not think in terms of linguistic States which has proved artificial. Let there be devices on the basis of resources and potentialities in this regard.

Secondly, the Constitution should be amended, if necessary, to enable the Central Government to enforce discipline in the use of river waters and to secure an equitable distribution of available water resources.

Thirdly, we should have a quasi-judicial body; in other words, a permanent inter-State River Water Commission whose awards should be made binding on the

parties to the dispute. The Central Government should, therefore, have the constitutional authority to enforce these awards. Otherwise, so long the Centre does not have such a device to enforce its writ on the States, the great talk of water grids, I am afraid, will remain a voice in the wilderness.

Finally, what I wish to convey to the Government is this. Let us not leave water to the visissitudes of politics and State chauvinism, and let us not forget that if we do not maintain our river systems in good shape, in a few years' time, we shall be witnessing silted rivers, more scarcity and more drought. It is, therefore, that I have suggested a high-power body to ensure proper river water management on national interest.

Sir, let me hope that the hon. Minister and the Government will use their good offices for an early and final settlement of the Cauvery River water dispute. With these words, I request the hon. Minister to give his reaction to my suggestions.

DR. K. L. RAO: I thank the hon. Member for the various suggestions which we shall keep in mind. I would only submit that the Government feel that water should be declared as a national asset and we are, therefore, thinking of bringing a measure by which we want to declare water as a national asset in the case of rivers, so that the Government will have considerable voice in directing its utilisation to the best interests of the country as a whole.

डा० लक्ष्मीनारायण बंसे (मंदसौर) : अध्यक्ष, महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बक्तव्य मे कहा है उन से बिबाद के सुधार की कोई गुंजाइश लगती नहीं है। जैसा कि फैक्ट फार्डिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय भी कहा गया है उन्हें केवल फैक्ट फार्डिंग तक ही सीमित रखा गया था और वह इस बात के लिए भी प्रतिबन्धित

[डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय]

ये कि वह किसी प्रकार का कोई रेकमेन्डेशन नहीं करे। उन्हे यह लिखा गया था—

"The fact-finding committee is only to collect data and not to make any recommendations"

उम म स्पष्ट उन्हे यह लिख दिया गया था। कमेटी के मामल जा कठिनाइया भी उत्पन्न हुई और उन्हो कहा था कि कुछ समय और चाहिए कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए, कमेटी न स्वयं उस बात व लिए समय भागा था कि और कुछ समय हम दिया जाये जिस से कि कुछ क्लेरिफिकेशन जा रह गए हैं कुछ डाटाज कलेक्ट करने की बात जा रह गई है उन सब का पूरा कर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। लेकिन वह समय उन्हें नहीं दिया गया। कमेटी न अपनी रिपोर्ट म हम बात का दर्शाया है कि उन का और अधिक समय दिया जाना ता शायद वह पूरा विवरण दे पाय। आज भी विवाद की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है।

जैन ही 29 अप्रैल का यह मीटिंग समाप्त हुई विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों द्वारा जा प्रतिनिधाय व्यक्त की गए वह अलग अलग प्रति क्रियाएँ हैं। तामिलनाडु के मुख्य मंत्री न अपनी प्रतिनिधाय व्यक्त की जैसा कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ उन्होंने कहा कि हमारा 1924 का ऐग्रीमेंट है वह ऐग्रीमेंट प्रागे भी यथावत बना रहना चाहिए जब तक कि उस म किसी प्रकार का संपादन न किया जाय या दूसरा ऐग्रीमेंट उस के स्थान पर न आए तब तक स्टेटस का रहना चाहिए। लेकिन उस व बिपरीत मैमर के मुख्य मंत्री का कहना यह है कि चाह किसी प्रकार का ऐग्रीमेंट हा या न हा, 1924 का ऐग्रीमेंट ता 1974 म समाप्त हो जायेगा हमारे यहाँ पर चलन वाली तीन परियाजनाएँ—कम्बनी, हेमावनी और सारंगी ये तीनों परियाजनाएँ यथावत चलेंगी। इस म किसी प्रकार की कोई राक नहीं की जायेगी जब कि तामिलनाडु के मुख्य मंत्री का आरोप है कि इन परियाजनाओं के कार्यान्वित हो जाने से उनका हानि होगी यद्यपि ये बहुत लम्बे समय

से चल रही हैं जिससे कम्बनी के बारे में तो प्लानिंग कमीशन का अधूरापन भी है, दूसरे के बारे में कोई अधूरापन नहीं है, लेकिन तामिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा हेमावनी के बारे में भी यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार उस के बारे में किसी न किसी प्रकार से उस को सहायता करते हुए, तथा आवश्यक धनराशि से मदद करते हुए अपना काम कर रही है और तामिलनाडु के पक्ष को कमजोर करने की चेष्टा कर रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह एक छोटा सा जल का विवाद है जो इन लम्बे समय से चला आ रहा है। इनका समय फीकट फार्डिंग में लगा। हम के बाद फिर कहने हैं कि वा महीने या तीन महीने बाद कोई मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन होगा ता कोई विचार करेंगे। फिर से रिपोर्ट मांगी जायेगी। कुछ प्रकाशित नक्शे हैं कुछ अप्रकाशित नक्शे हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो अब तक सामने नहीं लाए गए हैं। उन दस्तावेजों का देख कर फिर उम व बारे में कोई प्रश्न विना साधी जायेगी। ता इनके अंदर कोई विवाद का हल तत्काल निकल सक हम प्रकार की स्थिति नहीं लगती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस विवाद का हल करने के बारे में कोई ऐसा फारमूला गड्ढा करने वाले हैं नेशनल इम्पीरिकल फारमूला जिस के आधार पर जिस में कि राष्ट्रीय स्तर पर हम के ऊपर विचार किया जा सक? जैसा कि अभी सुझाव भी आया है हम जल का राष्ट्रीय सम्पत्ति मान कर के और राष्ट्रीय स्तर पर साच कर के इस विवाद का हल कर सकें इस प्रकार का कोई विचार क्या आप रखते हैं? क्योंकि केवल यह काबेरी के विवाद की बात नहीं है। नर्बदा का विवाद अलग चल रहा है। वह भी एक लम्बे समय से चल रहा है जिस में मध्य प्रदेश का अपना पक्ष है और गुजरात का अपना पक्ष है। मध्य प्रदेश के लोग सोचते हैं कि हमारी इसमें बहुत हानि हो रही है, हमारा बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड इस में चला जायेगा। लाखों व्यक्ति बेधबहार हो जायेंगे। हजारों किसान मारे मारे फिरेंगे। गुजरात के लोग कहते हैं कि हमारा

बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और हमारी बहुत अच्छी सिंचाई की क्षमता बढ़ जायेगी। बहुत अच्छा हमारा प्रदेश हरा भरा बन जायेगा। अपना अपना पक्ष है। लेकिन केन्द्रीय सरकार जानबूझ कर ऐसे विवाद खड़ी करती है और विवाद को बनाए रखना चाहती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश का है, बानसागर और सोन नदी का झगड़ा चला आ रहा है। उस का भी विवाद पड़ा हुआ है। लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बैठते हैं और बार बार विचार करते हैं। कई बार विचार हुआ। लेकिन उसके बारे में कोई निष्पत्ति नहीं हुआ। इस प्रकार मैं हमारे देश के अंदर जो जल प्रवाह हो रहा है जिस का हम उपयोग कर सकते हैं वह हम नहीं कर पा रहे हैं। आज बागों तरफ पानी की कमी है। जगह जगह पानी की कटौती की वजह से हमें बहुत काफी कठिनाइयां हो रही हैं। इरीगेशन फैमिलिटीज कही पर पाच परसेंट, कही दस परसेंट और कहीं आठ परसेंट है। पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाये तो पूरे देश भर के अंदर आठ या दस प्रतिशत से ज्यादा इरीगेशन फैमिलिटीज नहीं है।

ऐसी हालत में ऐसे मामलों के अंदर सरकार दिखाई करे और इसके बारे में कोई सख्त कार्यवाही न करे, यह ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यूरोप के अंदर डैन्यूब नदी बहुत बड़ी है जो यूरोप के कई देशों के अंदर से होकर बहती हुई गुजरती है। वहां पर समझौता हो सकता है। परस्पर एक दूसरे देश जल का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर दो तीन प्रदेश मिल कर जल का बंटवारा नहीं कर सकते हैं और आप करवाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार के विवाद बने रहें ताकि यह समस्या खड़ी रहे और लोग बार बार आप के पास आए। मैं एक बात और मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आखिर यह जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन वह बुलाने जा रहे हैं वह कब बुला रहे हैं और फैक्ट फार्डिंग कमेटी को फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं तो यही समिति होगी, उसके सदस्य

यही होंगे या कुछ नये लोगों को इस में लेने जा रहे हैं? आप यह समिति कब तक पुनर्गठित करने जा रहे हैं? और फिर जब तक कि फैक्ट फार्डिंग कमेटी आप रिवाइव नहीं करने है जब तक कोई नया गठन उसका नहीं हो जाता है, जब तक कि आप अपना कोई निर्णय नहीं देते हैं तब तक क्या 1924 का ऐग्रीमेंट यथावत कायम रहेगा या जैसा कि मैसूर राज्य ने जो कहा है कि हम अपनी परियोजनाएं यथावत चालू रखेंगे तो वह रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे? उसके कारण तामिलनाडु पर उस का कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? या मैसूर के अंदर उससे कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? क्यों कि मैसूर का कहना है कि हम जो जितना जल मिलना चाहिए और जितना जल मिल रहा था, जितने के हम अधिकारी थे, हम उतने का ही उपयोग कर रहे हैं, हम उस से अधिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैसूर वाले यह कहते हैं। लेकिन इन परियोजनाओं के बाद भी क्या उन का यह दावा सही है? और यदि सही है तो उन को यह हक मिलना चाहिए। यदि तामिलनाडु के ऊपर इस का विपरीत अंतर पड़ता है तो सरकार को उस को भी देखना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर चाहता हूँ कि भविष्य में इन सभी बातों के उपर ध्यान रखते हुए वह कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं? और जो स्पष्ट मैंने कहा 1924 के ऐग्रीमेंट के बारे में उस ऐग्रीमेंट को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, उस के बारे में भी बताएं। जा मैसूर की परियोजना है उसके बारे में उन का क्या विचार है और केवल ने जो अपना दावा प्रस्तुत किया है उस के बारे में उनका क्या विचार है?

वर्तमान कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अब जो जल प्राप्त हो रहा है वह 21 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राप्त हो रहा है, लेकिन 35 मिलियन क्यूबिक मीटर का दावा किया जा रहा है, 14 मिलियन कैसे बढ़ गया यह कहा से आवेगा? इस के बारे में क्या ओवरलैपिंग हो रही है, हमारे प्रदेशों ने अपने दावे बढ़ा बढ़ा कर रखे हैं, इन सब मामलों को आप कब तक समाप्त कर पायेंगे? कृपया उक्त तथ्यों का स्पष्ट उत्तर दें।

*Cauvery Waters (CA)*

DR K L RAO Sir, I do not know what exactly the Chief Ministers said outside the meeting. But this is what they have agreed to and, according to their statement. There was a general consensus on the total yield of the river as given in the Fact-Finding Committee's report. The Committee has been asked to furnish clarifications on some other points after such verification as is found necessary. The Chief Ministers agreed to meet at a later date to continue the discussions and explore the possibilities of arriving at a settlement, is agreed upon on 31st May, 1972.

This was the statement issued after the meeting. Therefore I expect that after the clarifications in respect of certain points that are found necessary are received, they will be able to discuss them and arrive at an amicable solution. As I submitted we are expecting verified data for the committee in one or two months time. Immediately after that Chief Ministers will meet and I hope that there would be good progress in finding a solution.

As regards the observations made by the hon Member in regard to inter State disputes in a country like ours with so many rivers flowing through many States the disputes are very small in number. Most of these disputes would be solved. In the case of the Narmada water dispute the concerned States are awaiting the award of the Prime Minister. As regards Bansagar Dam on the river Son, we are continuously discussing it. We hope that a solution in the best interests of the States, would be evolved.

As regards river water disputes I should say that there are not so many disputes pending before tribunals. All this is a very healthy sign. We are able to adjust ourselves on such a vital matter. Similarly, in the case of Cauvery water, this is of course a difficult problem, the demand for water by the States is very much more than available in the river, rightly so. That shows that they are interested in improving

the irrigation and they want water for that purpose. It is a very desirable thing. It is in this context that a national water grid is necessary so that water may flow to deficit areas of the States. I feel that we should congratulate ourselves that there have not been many water disputes.

12.34 Hrs.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of Delhi Transport Corporation 1971-72, Annual Report and certified Accounts of Shipping Development Fund Committee for 1971-72, Delhi Motor Vehicles (2nd Amdt.) Rules, 1972 and notifications under Motor Vehicles Act, 1939 in respect of Andhra Pradesh.

## THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR)

I beg to lay on the Table —

- (1) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Delhi Transport Corporation New Delhi for the year 1971-72 under sub-section (3) of section 35 of the Road Transport Corporations Act 1950. [Placed in Library See No IT-4964/73]
- (2) A copy of the Report and Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Shipping Development Fund Committee for the year 1971-72 together with the Audit Report thereon, under sub-section (6) of section 16 of the Merchant Shipping Act, 1958. [Placed in Library See No IT-4965/73]
- (3) A copy of the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No F 3 (28)/72 Tpt in Delhi Gazette dated the 1st January, 1973 under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [Placed in Library See No IT-4966/73]